भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2274**
(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

**अवसंरचना संबंधी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का उपयोग**

2274. **श्री सी. एम. रमेशः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) क्या सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 25,000 करोड़ रुपये के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उस प्रस्तावित अवसंरचना का ब्यौरा क्या है, जिस पर उक्त आय का निवेश किया जाएगा; और
(घ) सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से 2022-23 और 2023-24 में जुटाए गए क्रमशः 16,000 करोड़ रुपये और 20,000 करोड़ रुपये के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)**

(क) से (घ): हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने हेतु सरकार के समग्र बाजार उधार के भाग के रूप में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (01 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024) के लिए अपने उधार संबंधी कैलेंडर में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाने के संबंध में अधिसूचित किया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करके क्रमशः 16,000 करोड़ रुपये और 20,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाई हैं। इन बॉन्ड्स से प्राप्त आय को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवासन और शहरी मामले, रेलवे आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की पात्र हरित योजनाओं/परियोजनाओं के तहत आवंटित/उपयोग किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा जारी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के फ्रेमवर्क के अनुसार अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता (कार्बन इंटेसिटी) को कम करने में मदद करते हैं।

**********